

EXAM GENIUS
Presents
GENIUS
CURRENT
AFFAIRS

In Bilingual
26 & 27 October 2025



India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK | RAILWAY Exam

Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !



Ques: Which banks provided the \$215 million term loan to AI Fleet Services IFSC for financing six Boeing 777-300 ER aircraft for Air India?

कौन से बैंकों ने एयर इंडिया के लिए छह बोइंग 777-300 ER विमानों के वित्तपोषण हेतु AI Fleet Services IFSC को \$215 मिलियन का टर्म लोन दिया?

- A) Standard Chartered and Bank of India / स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बैंक ऑफ इंडिया
- B) State Bank of India and Axis Bank / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक
- C) HDFC Bank and ICICI Bank / एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक
- D) Citibank and Kotak Mahindra Bank / सिटीबैंक और कोटक महिंद्रा बैंक
- E) Punjab National Bank and IDBI Bank / पंजाब नेशनल बैंक और आईडीबीआई बैंक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- A \$215 million term loan was provided to AI Fleet Services IFSC (AIFS), the leasing subsidiary of Tata Group-owned Air India, based in GIFT City, for financing six Boeing 777-300 ER aircraft to be leased to Air India.
- \$215 मिलियन का टर्म लोन AI Fleet Services IFSC (Tata Group-owned Air India की लीजिंग सहायक कंपनी) को GIFT सिटी में स्थित, छह बोइंग 777-300 ER विमानों के वित्तपोषण के लिए दिया गया।
- The loan was jointly given by Standard Chartered and Bank of India (BoI), with Standard Chartered acting as the lead structuring bank.
- यह लोन स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड लीड स्ट्रक्चरिंग बैंक के रूप में कार्य कर रहा था।
- Both banks also served as Mandated Lead Arrangers and Bookrunners for the transaction.
- दोनों बैंकों ने इस लेनदेन के लिए मंडेटेड लीड अरेंजर और बुकरनर के रूप में भी काम किया।
- The financing will enable Air India to expand its fleet and support its operational and leasing plans.
- यह वित्तपोषण एयर इंडिया को अपने विमान बेड़े का विस्तार करने और परिचालन एवं लीजिंग योजनाओं का समर्थन करने में सक्षम बनाएगा।





Ques: ICICI Bank has partnered with which institution to construct a new cancer care centre in Maharashtra?

महाराष्ट्र में नया कैंसर केयर सेंटर बनाने के लिए ICICI बैंक ने किस संस्थान के साथ साझेदारी की है?

- A) AIIMS Delhi / एम्स दिल्ली
- B) Tata Memorial Centre (TMC) / टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी)
- C) Apollo Hospitals / अपोलो हॉस्पिटल्स
- D) Fortis Healthcare / फोर्टिस हेल्थकेयर
- E) Medanta Hospital / मेदांता हॉस्पिटल

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- ICICI Bank has partnered with the Tata Memorial Centre (TMC) to build a new cancer care building named 'ICICI Foundation Block for Radiation Oncology' at ACTREC, Navi Mumbai, Maharashtra.
- ICICI बैंक ने टाटा मेमोरियल सेंटर (TMC) के साथ मिलकर नवी मुंबई, महाराष्ट्र स्थित ACTREC परिसर में 'ICICI फाउंडेशन ब्लॉक फॉर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी' नामक नए कैंसर केयर भवन के निर्माण की शुरुआत की है।
- The ₹625 crore project is funded through ICICI Bank's CSR contribution and will include advanced radiation therapy centres equipped with cutting-edge technologies.
- यह ₹625 करोड़ की परियोजना ICICI बैंक के CSR योगदान से वित्तपोषित है और इसमें अत्याधुनिक रेडिएशन थेरेपी सुविधाएं शामिल होंगी।
- The initiative is part of ICICI Bank's ₹1,800 crore commitment to TMC for constructing three cancer care buildings — in Navi Mumbai (Maharashtra), Mullanpur (Punjab), and Visakhapatnam (Andhra Pradesh).
- यह पहल ICICI बैंक की ₹1,800 करोड़ की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके तहत तीन अत्याधुनिक कैंसर केयर भवन नवी मुंबई, मुल्लनपुर और विशाखापट्टनम में बनाए जा रहे हैं।
- The new facility is expected to be completed by 2027.
- इस नई सुविधा को 2027 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है।





Ques: As per the Notaries (Amendment) Rules, 2025, what is the new maximum number of Notaries allowed to be appointed in Gujarat?

नोटरी (संशोधन) नियम, 2025 के अनुसार गुजरात में नियुक्त किए जाने वाले नोटरी की अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई है?

- A) 2,900
- B) 4,000
- C) 5,000
- D) 6,000
- E) 7,000

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Department of Legal Affairs notified the Notaries (Amendment) Rules, 2025 through G.S.R. 763(E) published in the Extraordinary Gazette of India, exercising powers under Section 15 of the Notaries Act, 1952.
- विधि कार्य विभाग ने नोटरी (संशोधन) नियम, 2025 को भारत के राजपत्र (G.S.R. 763(E)) में अधिसूचित किया, जो नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया।
- The amendment revised the maximum number of Notaries to be appointed by certain State Governments under the Notaries Rules, 1956.
- इस संशोधन के तहत कुछ राज्यों में नियुक्त किए जाने वाले नोटरी की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है।

Updated limits under Notaries (Amendment) Rules, 2025:

Gujarat: 2,900 → 6,000

Tamil Nadu: 2,500 → 3,500

Rajasthan: 2,000 → 3,000

Nagaland: 200 → 400

- A Notary is a public official authorized to verify, authenticate, and certify legal documents, witness signatures, and administer oaths.
- नोटरी एक सार्वजनिक अधिकारी होता है जो कानूनी दस्तावेजों को सत्यापित, प्रमाणित और हस्ताक्षरित करने का कार्य करता है तथा शपथ और घोषणाएं दिलाने के लिए अधिकृत होता है।





Ques: According to RBI data, by how much did India's outward remittances for education fall in August 2025 (year-on-year)?

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, अगस्त 2025 में शिक्षा हेतु विदेश भेजी गई राशि में वर्ष-दर-वर्ष कितनी गिरावट आई?

- A) 12%
- B) 19%
- C) 23.8%
- D) 28%
- E) 17.7%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- As per RBI's August 2025 data, India's outward remittances for education abroad fell 23.8% year-on-year to \$0.32 billion, down from \$0.42 billion in August 2024.
- आरबीआई के अगस्त 2025 के आंकड़ों के अनुसार, विदेश में शिक्षा हेतु भेजी गई राशि वर्ष-दर-वर्ष 23.8% घटकर \$0.32 बिलियन रह गई, जो अगस्त 2024 में \$0.42 बिलियन थी।
- This is the lowest monthly figure since August 2017.
- यह अगस्त 2017 के बाद सबसे कम मासिक प्रेषण राशि है।
- Travel-related remittances also declined by 19%, due to tighter immigration and visa norms in countries like the US, UK, and Europe.
- यात्रा-संबंधी प्रेषण में भी 19% की गिरावट आई, जो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जैसे देशों में कड़े आव्रजन और वीज़ा नियमों के कारण हुई।





Ques: What proposal has the SEBI working group headed by R.S. Gandhi recently made regarding clearing corporations?

हाल ही में R.S. गांधी के नेतृत्व वाले SEBI कार्य समूह ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के संबंध में क्या प्रस्ताव रखा है?

- A) Decrease transaction charges / लेन-देन शुल्क घटाना
- B) Merge clearing corporations / क्लियरिंग कॉर्पोरेशन्स का विलय करना
- C) Abolish transaction charges / लेन-देन शुल्क समाप्त करना
- D) Keep broker charges higher / ब्रोकर शुल्क बढ़ाना
- E) Increase transaction charges / लेन-देन शुल्क बढ़ाना

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- A SEBI-constituted working group, headed by Rama Subramaniam (R.S) Gandhi, former Deputy Governor of RBI, has proposed increasing transaction charges for clearing corporations such as NSE Clearing Limited.
- SEBI द्वारा गठित कार्य समूह, जिनका नेतृत्व पूर्व आरबीआई उप-गवर्नर रामा सुब्रमण्यम (R.S) गांधी कर रहे हैं, ने NSE Clearing Limited जैसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशनों के लिए लेनदेन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।
- SEBI clarified that broker charges will remain unchanged.
- SEBI ने स्पष्ट किया कि ब्रोकर्स के शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा।
- The move aims to strengthen the financial independence and balance sheets of these clearing corporations.
- इस कदम का उद्देश्य इन क्लियरिंग कॉर्पोरेशनों की वित्तीय स्वतंत्रता और बैलेंस शीट को मजबूत करना है।
- Currently, NSE Clearing receives about 5%–6% of the fees collected by NSE from members, and the revision is expected to raise their share to around 25% or slightly higher.
- वर्तमान में, NSE Clearing को NSE द्वारा सदस्यों से वसूले जाने वाले शुल्क का लगभग 5%–6% मिलता है, और प्रस्तावित संशोधन से यह हिस्सा लगभग 25% या उससे थोड़ा अधिक होने की उम्मीद है।





Ques: What recent change has the Reserve Bank of India (RBI) made regarding the ₹10,000 crore ceiling on bank loans to a single corporate entity?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किसी एक कॉर्पोरेट इकाई को दिए जाने वाले 10,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की सीमा के संबंध में क्या बदलाव किया है?

- A) Ceiling reduced to ₹5,000 crore / सीमा 5,000 करोड़ रुपये कर दी गई
- B) Ceiling removed entirely / सीमा पूरी तरह हटा दी गई
- C) Ceiling increased to ₹15,000 crore / सीमा 15,000 करोड़ रुपये कर दी गई
- D) No change to existing ceiling / मौजूदा सीमा में कोई बदलाव नहीं
- E) Ceiling replaced by exposure ratio / सीमा को एक्सपोज़र रेशियो से बदल दिया गया

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The RBI has removed the ₹10,000 crore ceiling on bank loans to a single corporate entity, effective from 1 April 2026, giving banks greater lending flexibility.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसी एक कॉर्पोरेट इकाई को दिए जाने वाले 10,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की सीमा हटा दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी, जिससे बैंकों को अधिक ऋण देने की स्वतंत्रता मिलेगी।
- Earlier guidelines (2016) limited concentration risk and encouraged corporates to diversify funding, requiring higher provisions and risk weights if the cap was breached.
- पहले 2016 के दिशानिर्देशों ने सांद्रण जोखिम को सीमित किया और कॉर्पोरेट्स को वित्त पोषण विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया, और यदि सीमा पार होती तो अधिक प्रावधान और जोखिम भार लागू करना पड़ता।
- Going forward, the Large Exposures Framework (LEF) will manage concentration risk at the bank level, while systemic risk will be monitored through macroprudential tools.
- अब Large Exposures Framework (LEF) बैंक स्तर पर सांद्रण जोखिम को नियंत्रित करेगा, जबकि प्रणालीगत जोखिम को मैक्रोप्रूडेंशियल टूल्स से मॉनिटर किया जाएगा।
- Under LEF, total exposure to a single borrower cannot exceed 20% of Tier 1 capital, and 25% in case of a corporate group.
- LEF के तहत किसी एक उधारकर्ता के लिए कुल एक्सपोज़र Tier 1 कैपिटल का 20% से अधिक नहीं हो सकता, और कॉर्पोरेट समूह के लिए यह सीमा 25% है।





Ques: How many bird species were recorded in the latest survey at Kaziranga National Park and Tiger Reserve?

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में हालिया सर्वेक्षण में कितनी पक्षी प्रजातियाँ दर्ज की गईं?

- A) 128
- B) 146
- C) 172
- D) 155
- E) 139

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- In the latest bird survey conducted at Kaziranga National Park and Tiger Reserve (Assam), a total of 146 bird species comprising 1,919 individual birds were recorded across five key locations — Agoratoli, Gamiri, Panbari, Panpur, and Laokhowa Wildlife Sanctuary.
- असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में किए गए हालिया पक्षी सर्वेक्षण में कुल 146 पक्षी प्रजातियाँ और 1,919 पक्षी दर्ज किए गए, जो अगोरेटोली, गामीरी, पानबारी, पानपुर और लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य में पाए गए।
- Among them, Agoratoli range recorded the highest diversity with 89 species, followed by Gamiri and Panbari (59 each), Panpur (55), and Laokhowa (37).
- इनमें से अगोरेटोली क्षेत्र में सबसे अधिक विविधता (89 प्रजातियाँ) दर्ज की गई, जबकि गामीरी और पानबारी में 59-59, पानपुर में 55 और लाओखोवा में 37 प्रजातियाँ पाई गईं।
- Officials also confirmed sightings of several important resident and migratory bird species, highlighting Kaziranga's ecological richness.
- अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की कि कई महत्वपूर्ण स्थानीय और प्रवासी पक्षी प्रजातियाँ दर्ज की गईं, जो काजीरंगा की पारिस्थितिक समृद्धि को दर्शाती हैं।





Ques: What is 'Ola Shakti' recently launched by Ola Electric?

ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में 'ओला शक्ति' के रूप में क्या लॉन्च किया?

- A) A new electric scooter / एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर
- B) A residential Battery Energy Storage System (BESS) / एक आवासीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)
- C) A solar-powered charging station / एक सौर ऊर्जा चालित चार्जिंग स्टेशन
- D) A lithium mining project / लिथियम खनन परियोजना
- E) An EV software platform / एक ईवी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Ola Electric Mobility Limited launched 'Ola Shakti', a residential Battery Energy Storage System (BESS) powered by its indigenous 4680 "Bharat Cell" technology, marking its entry into the residential energy storage segment.
- ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने 'ओला शक्ति' लॉन्च किया, जो कि इसके स्वदेशी 4680 "भारत सेल" तकनीक से संचालित आवासीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) है, और यह आवासीय ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में इसका प्रवेश है।
- The 4680 Bharat Cell is a cylindrical lithium-ion cell developed by Ola for its electric vehicles, designed for high energy density, efficiency, and thermal stability.
- 4680 भारत सेल एक बेलनाकार लिथियम-आयन सेल है, जिसे ओला ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विकसित किया है, जो उच्च ऊर्जा घनत्व, दक्षता और तापीय स्थिरता के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- Deliveries of Ola Shakti are expected to begin in January 2026.
- 'ओला शक्ति' की डिलीवरी जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है।





Ques: Who has been appointed to the Supreme Court panel tasked with formulating an equal opportunity policy for the protection of transgender rights?

ट्रान्सजेंडर अधिकारों की सुरक्षा हेतु समान अवसर नीति तैयार करने के लिए गठित सर्वोच्च न्यायालय की समिति में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Grace Banu / ग्रेस बानू
- B) Laxmi Narayan Tripathi / लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी
- C) Vyjayanthi Vasanta Mogli / वजयंती वसंथा मोगली
- D) Nithya Rajshekhar / नित्या राजशेखर
- E) Akkai Padmashali / अक्काई पद्मशाली

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Trans rights activist Akkai Padmashali has been appointed to a Supreme Court panel formed to draft an equal opportunity policy for the protection of transgender rights.
- ट्रान्सजेंडर अधिकार कार्यकर्ता अक्काई पद्मशाली को ट्रान्सजेंडर अधिकारों की सुरक्षा हेतु समान अवसर नीति तैयार करने के लिए गठित सर्वोच्च न्यायालय की समिति में नियुक्त किया गया है।
- She is the first transgender person from Karnataka to serve on such a committee.
- वह कर्नाटक की पहली ट्रान्सजेंडर व्यक्ति हैं जिन्हें इस प्रकार की समिति में शामिल किया गया है।
- The panel is headed by Justice Asha Menon, a retired judge of the Delhi High Court.
- इस समिति की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आशा मेनन कर रही हैं।
- Other members include Grace Banu, Vyjayanthi Vasanta Mogli, Sourav Mandal, Nithya Rajshekhar, and Sanjay Sharma.
- समिति के अन्य सदस्यों में ग्रेस बानू, वजयंती वसंथा मोगली, सौरव मंडल, नित्या राजशेखर और संजय शर्मा शामिल हैं।





Ques: As per the IUCN's latest Red List update 2025, how many Indian bird species were assessed?

IUCN की नवीनतम रेड लिस्ट अपडेट 2025 के अनुसार, भारत की कितनी पक्षी प्रजातियों का मूल्यांकन किया गया?

- A) 4
- B) 8
- C) 12
- D) 20
- E) 15

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- In the IUCN Red List 2025, a total of 1,360 bird species worldwide were assessed, including 12 species from India, out of which 4 Indian species were uplisted due to habitat loss in open natural ecosystems.
- IUCN रेड लिस्ट 2025 में दुनिया की 1,360 पक्षी प्रजातियों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 12 भारत से हैं, और उनमें से 4 प्रजातियों की स्थिति और गंभीर बताई गई है क्योंकि उनके खुले प्राकृतिक आवास तेजी से नष्ट हो रहे हैं।
- India's open natural ecosystems—such as grasslands, semi-arid regions, deserts, croplands, hilly scrublands, and fallow lands—are increasingly under threat due to habitat loss and land-use change.
- भारत के घास के मैदान, अर्ध-शुष्क क्षेत्र, रेगिस्तान, कृषि भूमि, झाड़ीदार पहाड़ी क्षेत्र और परती भूमि जैसी प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालियाँ लगातार खतरे में हैं।
- The uplisting reflects rapid degradation of open habitats due to urbanisation, agriculture expansion, and infrastructure development.
- यह अपलिस्टिंग शहरीकरण, कृषि विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण खुले आवासों के तेजी से बिगड़ने को दर्शाती है।
- The IUCN Red List was launched to assess the global conservation status of species, ranging from Least Concern (LC) to Extinct (EX).
- IUCN रेड लिस्ट का उद्देश्य प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन करना है, जिसमें सबसे कम चिंता (LC) से लेकर विलुप्त (EX) तक की श्रेणियाँ शामिल हैं।





Ques: Which major labour reform did Saudi Arabia announce in June 2025?

सऊदी अरब ने जून 2025 में कौन सा प्रमुख श्रम सुधार की घोषणा की?

- A) Introduction of a minimum wage for all workers / सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन की शुरुआत
- B) End of the Kafala sponsorship system / कफाला प्रायोजन प्रणाली का अंत
- C) Mandatory work permits for domestic workers / घरेलू कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कार्य परमिट
- D) Reduction in working hours for migrant workers / प्रवासी श्रमिकों के लिए कार्य समय में कमी
- E) Implementation of social security for foreign workers / विदेशी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लागू करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Saudi Arabia announced the end of its decades-old Kafala system, a labour sponsorship model that controlled the lives of millions of migrant workers for over seventy years.
- सऊदी अरब ने अपने दशकों पुराने कफाला प्रणाली का अंत किया, जो सत्तर वर्षों से लाखों प्रवासी श्रमिकों के जीवन को नियंत्रित करती थी।
- The reform, unveiled in June 2025, is one of the most sweeping changes to the Gulf's labour framework and is expected to directly benefit around 13 million foreign workers, including over 2.6 million Indians.
- यह सुधार, जो जून 2025 में घोषित किया गया, खाड़ी क्षेत्र के श्रम ढांचे में सबसे व्यापक बदलावों में से एक है और लगभग 1.3 करोड़ विदेशी श्रमिकों, जिनमें 26 लाख से अधिक भारतीय शामिल हैं, को सीधे लाभ पहुंचाने की उम्मीद है।
- The word "Kafala" means "sponsorship" in Arabic and referred to a structure where a local employer (Kafeel) took legal responsibility for a foreign worker's visa and residency.
- "कफाला" शब्द अरबी में "प्रायोजन" का अर्थ देता है और यह उस संरचना को संदर्भित करता था जिसमें स्थानीय नियोक्ता (काफील) प्रवासी श्रमिक के वीजा और निवास की कानूनी जिम्मेदारी लेता था।
- The announcement is part of Crown Prince Mohammed bin Salman's Vision 2030 initiative to modernize Saudi Arabia's economy and labour policies.





Ques: When was the Pradhan Mantri Schools for Rising India (PM-SHRI) scheme launched?

प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना कब शुरू की गई थी?

- A) August 15, 2022
- B) September 7, 2022
- C) January 26, 2023
- D) October 2, 2022
- E) November 14, 2022

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The PM-SHRI Scheme was launched on September 7, 2022 by the Government of India under the Ministry of Education.
- पीएम-श्री योजना को 7 सितंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था।
- The scheme aims to upgrade over 14,500 schools into model “Green Schools” promoting quality, inclusive, and sustainable education.
- इसका उद्देश्य 14,500 से अधिक विद्यालयों को “ग्रीन स्कूल” में परिवर्तित कर गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और सतत शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- With Kerala joining the scheme, the implementation is expected to strengthen school infrastructure, teacher training, and student welfare in the state.
- केरल के जुड़ने से योजना के कार्यान्वयन से राज्य में विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक प्रशिक्षण और छात्र कल्याण को सशक्त करने की उम्मीद है।





Ques: What initiative has NHA announced to improve road maintenance and asset management on National Highways?

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क रखरखाव और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधारने के लिए NHA ने कौन-सी पहल की घोषणा की है?

- A) Deployment of Automated Toll Booths / स्वचालित टोल बूथ तैनात करना
- B) Installation of Smart Traffic Lights / स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स लगाना
- C) Deployment of Network Survey Vehicles (NSVs) / नेटवर्क सर्वे वाहन (NSVs) तैनात करना
- D) Launch of Highway Patrol Drones / हाइवे पेट्रोल ड्रोन लॉन्च करना
- E) Construction of Additional Service Lanes / अतिरिक्त सेवा लेन का निर्माण

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The National Highways Authority of India (NHA) has deployed Network Survey Vehicles (NSVs) across 23 states to collect, process, and analyse detailed data on road inventory and pavement conditions.
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHA) ने 23 राज्यों में नेटवर्क सर्वे वाहन (NSVs) तैनात किए हैं, जो सड़क सूची और पैवमेंट की स्थिति का विस्तृत डेटा एकत्रित, प्रोसेस और विश्लेषण करेंगे।
- These vehicles cover a total stretch of 20,933 kilometres, aiming to improve road maintenance and asset management.
- ये वाहन कुल 20,933 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करेंगे, जिसका उद्देश्य सड़क रखरखाव और परिसंपत्ति प्रबंधन में सुधार करना है।
- Data gathered by NSVs will be uploaded to NHA's AI-enabled 'Data Lake' platform for advanced analysis and informed decision-making.
- NSVs द्वारा एकत्रित डेटा NHA के AI-सक्षम 'Data Lake' प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा, ताकि उन्नत विश्लेषण और सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सके।





Ques: Which city in India became the first to fully operationalize a Real Time Flood Forecasting and Spatial Decision Support System?

भारत का कौन सा शहर पहली बार वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान और स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली को पूरी तरह से कार्यान्वित करने वाला बना?

- A) Mumbai / मुंबई
- B) Chennai / चेन्नई
- C) Kolkata / कोलकाता
- D) Delhi / दिल्ली
- E) Bengaluru / बेंगलुरु

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Chennai became the first city in India to fully operationalize a Real Time Flood Forecasting and Spatial Decision Support System, enhancing its flood preparedness and response capabilities.
- चेन्नई भारत का पहला शहर बन गया जिसने वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान और स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली को पूरी तरह से लागू किया, जिससे बाढ़ तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत हुई।
- The system predicts and manages urban floods by integrating data from Automatic Rain Gauges, Automatic Weather Stations, Automatic Water Level Recorders, and Gate Sensors.
- यह प्रणाली ऑटोमैटिक रेन गेज, ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमैटिक वॉटर लेवल रिकॉर्डर और गेट सेंसर से डेटा एकीकृत करके शहरी बाढ़ का पूर्वानुमान और प्रबंधन करती है।
- The project was funded by the World Bank under the Project Development Grant Fund and managed by Tamil Nadu Urban Infrastructure Financial Services Limited.
- यह परियोजना वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ग्रांट फंड के तहत वित्त पोषित की गई थी और इसे तमिलनाडु अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने प्रबंधित किया।





Ques: Who has been appointed as the new President of the Indian Cricketers' Association (ICA)?

भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन (ICA) की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Mithali Raj / मिताली राज
- B) Jhulan Goswami / झूलन गोस्वामी
- C) Anjum Chopra / अंजुम चोपड़ा
- D) Diana Edulji / डायना एडुलजी
- E) Shantha Rangaswamy / शांतारंगास्वामी

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Former India women's cricket captain Shantha Rangaswamy has been appointed as the President of the Indian Cricketers' Association (ICA), becoming the first woman to lead the organization.
- भारत की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान शांतारंगास्वामी को भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन (ICA) की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और वह इस संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी हैं।
- She was the first woman cricketer to receive the Arjuna Award (1976) and also received the BCCI Lifetime Achievement Award for Women (2017).
- वह 1976 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर थीं और उन्हें 2017 में बीसीसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड (महिला वर्ग) से भी सम्मानित किया गया था।
- The Indian Cricketers' Association (ICA) is a non-profit company, incorporated on July 5, 2019, and recognized by the Board of Control for Cricket in India (BCCI) as the official association for former Indian cricketers.
- भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन (ICA) एक गैर-लाभकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 2019 को हुई थी और जिसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) द्वारा पूर्व क्रिकेटरों के आधिकारिक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है।





Ques: Which institution is developing India's first indigenously-designed 7-nanometer computer processor 'Shakti'?

भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया 7-नैनोमीटर कंप्यूटर प्रोसेसर 'शक्ति' किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है?

- A) IIT Bombay
- B) IISc Bengaluru
- C) IIT Madras
- D) DRDO
- E) ISRO

Answer: Option C

Explanation :

- India's first 7-nanometer computer processor 'Shakti' is being developed by a team at IIT Madras and is expected to be ready by 2028.
- भारत का पहला 7-नैनोमीटर कंप्यूटर प्रोसेसर 'शक्ति' आईआईटी मद्रास की टीम द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसके 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है।
- The indigenous chip can be produced locally in India once the chip fabrication plant (wafer fab) becomes operational.
- यह स्वदेशी चिप भारत में स्थानीय स्तर पर निर्मित की जा सकेगी, जब चिप निर्माण संयंत्र (वेफ़र फैब) चालू हो जाएगा।
- The processor will be used in IT servers and can later be deployed in computers, defense, communications, and strategic sectors.
- यह प्रोसेसर आईटी सर्वर में उपयोग किया जाएगा और बाद में इसे कंप्यूटर, रक्षा, संचार और सामरिक क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकेगा।
- Union Minister Ashwini Vaishnaw informed that India will transition from 28-nm to 7-nm technology for chip production.
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत अब 28-नैनोमीटर से 7-नैनोमीटर तकनीक की ओर अग्रसर होगा।
- The minister approved the IIT Madras team's proposal to begin indigenous production of the chipset for IT servers.
- मंत्री ने आईटी सर्वरों के लिए स्वदेशी चिपसेट उत्पादन शुरू करने के लिए आईआईटी मद्रास टीम के प्रस्ताव को मंजूरी दी।





Ques: Which event did the Indian Army host in 2025 to deliberate on the future of UN peacekeeping operations?

2025 में वैश्विक शांति सेना (UN Peacekeeping Operations) के भविष्य पर विचार करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा आयोजन किया?

- A) International Defence Expo 2025 / अंतर्राष्ट्रीय रक्षा एक्सपो 2025
- B) United Nations Troop Contributing Countries (UNTCC) Chiefs Conclave 2025 / संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदान देशों (UNTCC) प्रमुखों की बैठक 2025
- C) Global Military Leadership Summit 2025 / वैश्विक सैन्य नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2025
- D) Atmanirbhar Defence Technology Summit 2025 / आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक शिखर सम्मेलन 2025
- E) Strategic Peacekeeping Dialogue 2025 / रणनीतिक शांति सेना संवाद 2025

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Indian Army hosted the United Nations Troop Contributing Countries (UNTCC) Chiefs Conclave 2025 at the Manekshaw Centre in New Delhi, bringing together senior military leadership from 32 nations and UN officials.
- भारतीय सेना ने नई दिल्ली के मेनकशॉ सेंटर में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदान देशों (UNTCC) प्रमुखों की बैठक 2025 आयोजित की, जिसमें 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
- The theme of the conclave was “The Way Ahead for UN Peacekeeping Operations,” guided by the “4Cs” principles: Consultation, Cooperation, Coordination, and Capacity Building.
- इस बैठक का विषय था “UN Peacekeeping Operations के लिए आगे का मार्ग,” और इसे “4Cs” सिद्धांतों – परामर्श, सहयोग, समन्वय और क्षमता निर्माण – द्वारा मार्गदर्शित किया गया।
- Participants also visited Agra for an Integrated New Age Technology Demonstration by the Indian Army, showcasing indigenous next-generation equipment aligned with Atmanirbharata.
- प्रतिभागियों ने आगरा का दौरा भी किया, जहाँ भारतीय सेना द्वारा एकीकृत नई पीढ़ी की तकनीक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें आत्मनिर्भरता के अनुरूप स्वदेशी उन्नत उपकरण प्रदर्शित किए गए।





Ques: Under which Schedule will oral formulations containing more than 12% ethyl alcohol now be classified?

12% से अधिक एथिल अल्कोहल वाली मौखिक दवाओं को अब किस शेड्यूल के तहत वर्गीकृत किया जाएगा?

- A) Schedule G / शेड्यूल G
- B) Schedule H / शेड्यूल H
- C) Schedule H1 / शेड्यूल H1
- D) Schedule H2 / शेड्यूल H2
- E) Schedule X / शेड्यूल X

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Central Government has proposed that oral formulations containing more than 12% ethyl alcohol and sold in bottles over 30 ml be classified under Schedule H1 of the Drugs Rules, 1945.
- केंद्र सरकार ने 12% से अधिक एथिल अल्कोहल वाली मौखिक दवाओं, जो 30 मिलीलीटर से बड़ी बोतलों में बेची जाती हैं, को ड्रग्स रूल्स, 1945 के शेड्यूल H1 के तहत वर्गीकृत करने का प्रस्ताव रखा है।
- Schedule H1 covers prescription drugs requiring strict monitoring, including maintaining sales records and retaining prescriptions by pharmacies.
- शेड्यूल H1 में वे पर्चे वाली दवाएं शामिल हैं जिनकी कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है, जैसे बिक्री रिकॉर्ड बनाए रखना और फार्मेशियों द्वारा प्रिस्क्रिप्शन सुरक्षित रखना।
- This measure aims to prevent misuse of high-alcohol medicines, particularly among vulnerable populations.
- इस कदम का उद्देश्य उच्च-अल्कोहल दवाओं के दुरुपयोग को रोकना और संवेदनशील आबादी में नियंत्रण बढ़ाना है।
- Additionally, mandatory QR codes are being proposed for vaccines, antimicrobials, anti-cancer, narcotic, and psychotropic drugs to ensure authenticity and traceability.
- इसके अतिरिक्त, वैक्सीन, एंटीमाइक्रोबियल, एंटी-कैंसर, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक दवाओं पर प्रामाणिकता और ट्रेसिंग सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।





Ques: When was ASEAN established?

आसियान की स्थापना कब हुई थी?

- A) 15 August 1965
- B) 8 August 1967
- C) 12 March 1971
- D) 1 January 1975
- E) 5 June 1969

Answer: Option B

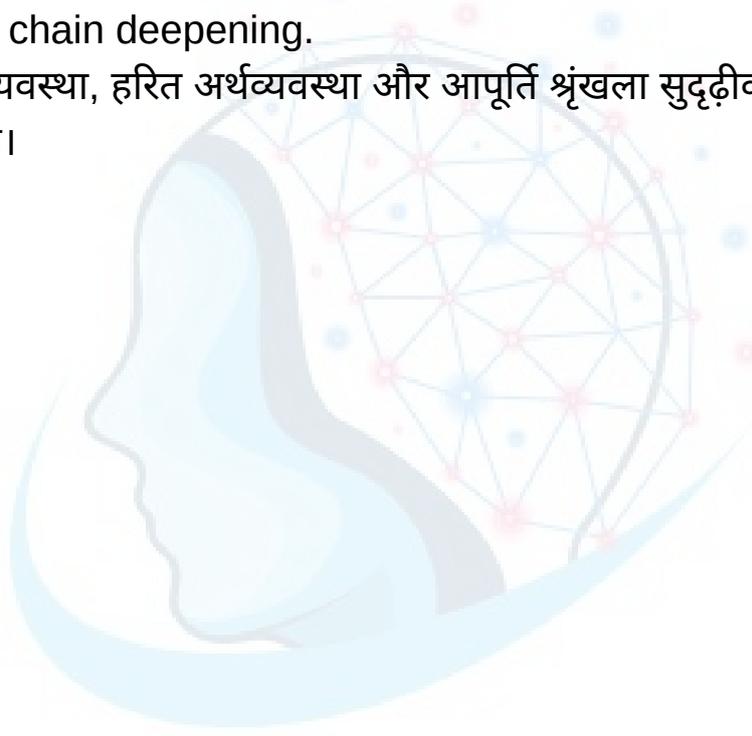
Explanation / व्याख्या:

- ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) was established on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand, through the signing of the ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) by its five founding members — Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand.
- आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन) की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के माध्यम से पांच संस्थापक देशों — इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा की गई थी।
- India and ASEAN members recently exchanged proposals on outstanding trade issues, as part of the ongoing review of the ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA), which both sides aim to conclude by the end of 2025.
- भारत और आसियान सदस्य देशों ने हाल ही में लंबित व्यापारिक मुद्दों पर प्रस्तावों का आदान-प्रदान किया, यह आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा का हिस्सा है, जिसे दोनों पक्ष 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
- India is seeking more balanced gains through greater market access in ASEAN countries such as Indonesia, Vietnam, Thailand, and Cambodia, especially for agricultural products, vehicles, and pharmaceuticals.
- भारत इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे आसियान देशों में कृषि उत्पाद, वाहन और दवाओं के लिए अधिक बाजार पहुंच के माध्यम से संतुलित लाभ चाहता है।
- The review may be officially announced at the ASEAN-India Summit in Kuala Lumpur later this month.
- समीक्षा पर आधिकारिक घोषणा इस महीने के अंत में कुआलालंपुर में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में की जा सकती है।





- India's counter proposal focuses on reducing its \$45.2 billion trade deficit with ASEAN, which has widened due to lower tariff cuts by ASEAN members and limited utilisation of FTA by Indian exporters.
- भारत का प्रतिप्रस्ताव आसियान के साथ अपने \$45.2 बिलियन व्यापार घाटे को कम करने पर केंद्रित है, जो आसियान सदस्यों द्वारा कम टैरिफ कटौती और भारतीय निर्यातकों द्वारा सीमित एफटीए उपयोग के कारण बढ़ा है।
- ASEAN also aims to strengthen cooperation in areas like digital economy, green economy, and supply chain deepening.
- आसियान डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान दे रहा है।



EXAM
Genius





Ques: What initiative did the Ministry of Health and Family Welfare launch to strengthen public health management of chemical emergencies?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रासायनिक आपात स्थितियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए कौन-सी पहल शुरू की?

- A) Launch of AI-based Health Surveillance System / एआई-आधारित स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली लॉन्च करना
B) Training modules on Public Health Management of Chemical Emergencies / रासायनिक आपात स्थितियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू करना
C) National Chemical Safety Policy / राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा नीति
D) Mobile Emergency Response Units / मोबाइल आपात प्रतिक्रिया इकाइयाँ
E) Chemical Waste Management Program / रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- PS Srivastava, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, launched specialized training modules on Public Health Management of Chemical Emergencies to strengthen national capacities in line with International Health Regulations 2005.
- पीएस श्रीवास्तव, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम 2005 के अनुरूप राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करने के लिए रासायनिक आपात स्थितियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किए।
- These modules are designed to equip public health professionals, healthcare workers, emergency responders, and policymakers with the necessary knowledge, skills, and operational tools.
- ये मॉड्यूल सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों और नीति निर्माताओं को आवश्यक ज्ञान, कौशल और कार्यात्मक उपकरण प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं।
- Developed by the National Centre for Disease Control in collaboration with NDMA and WHO India, the three modules focus on preparedness and response, pre-hospital management, and medical management of chemical emergencies.
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और WHO इंडिया के सहयोग से इन तीन मॉड्यूल को तैयार किया, जो तैयारी और प्रतिक्रिया, अस्पताल पूर्व प्रबंधन, और रासायनिक आपात स्थितियों के चिकित्सा प्रबंधन पर केंद्रित हैं।

